

Regular First Appeal (Against decree) No:14/2023  
Omprakash Vs. Narbda & Ors.  
Date of order: 19.3.2026

**COURT OF DISTRICT JUDGE, MERTA, DISTRICT: NAGAUUR [RAJASTHAN]**

[Presiding Officer: Arun K Beriwal]

**Targeted Case No: 10**

Regular First Appeal [Against decree] No: 14/2023

**IN THE MATTER OF**

Omprakash

S/o: Late Nathuram

Age- 68 years

R/o: Harsaur Tehsil-Degana

District Nagaur (Rajasthan)

.... Appellant

**Vs.**

1. Narbda  
Wife of Naurat  
Aged 45 years ..Respondent No.1
2. Paro  
D/o: Devkaran  
Aged 47 years ...Respondent No.2
3. Naurat  
S/o: Devkaran  
Aged 55 years ..Respondent No.3
4. Ramesh  
S/o: Devkaran  
Age: 53 years ...Respondent No.4
5. Kishore  
S/o: Devkaran  
Aged: 51 years ....Respondent No. 5

**All R/o:** Harsaur Tehsil-Degana

District Nagaur (Rajasthan)

Regular First Appeal (Against decree) No:14/2023  
 Omprakash Vs. Narbda & Ors.  
 Date of order: 19.3.2026

**Present :** Anil Diwakar Advocate for Appellants.

Rajjab Ali, Advocate for Respondent Nos.1 to 3

None appeared for Respondent nos. 4 to 5 despite service.

19.3.2026

### J U D G M E N T

1. That this a Regular First appeal against the final judgment & decree dated 4.8.2023 passed by the Court of Sr. Civil Judge, Merta in Civil Suit No:14/2012 whereby the suit filed by the Plaintiffs seeking Permanent Injunction was dismissed.

#### Plaint averments before Trial Court:-

2. That the Plaintiff-Jhuma & Omprakash filed a civil-suit before the Court of Sr. Civil Judge, Merta seeking Permanent injunction against the Defendants[Narmada, Paro, Navrat, Ramesh, Kishore, Dhannaram, Banshi & Sukhdev].
3. As per plaint averment & reply of Defendants in their written statement the Ld. Trial court noted the gravamen of dispute & cause of action as under:-

“ग्राम हरसौर में स्व. चन्द्राराम जी के नाम का पट्टासुदा भूखण्ड आया हुआ है जिसका पट्टा सं. 201 दिनांक 29.04.61 को ग्राम पंचायत हरसौर द्वारा जारी किया हुआ है एवं वादीगण मौके की स्थिति का नजरी नक्शा परिशिष्ट—क वाद के साथ पेश कर रहे हैं जो उक्त वाद का अभिन्न अंग होने से इसे उक्त वाद का भाग समझा जाये एवं उक्त नजरी नक्शे में उक्त सम्पूर्ण भूखण्ड मार्क ई एफ सी डी से दर्शित है एवं इसमें ए, बी, सी, डी वादीगण का बंटसुदा भूखण्ड है जिस बाबत वादीगण उक्त वाद प्रस्तुत कर रहे हैं। वादीगण के उक्त भूखण्ड मार्क ए, बी, सी, डी के पाड़ौस व नाप—चौप वाद पत्र के फिकरा नम्बर 3 के अनुसार है। वादीगण के उक्त भूखण्ड के उत्तरी तरफ गणपत मेघ ावाल के मकान की दीवार एवं दक्षिणी तरफ दौलत खां सिपाही के प्लॉट की पक्की दीवार निर्मित है एवं पुरबी तरफ वादीगण की दीवार थी जो अभी गिर चुकी है एवं नीव मौजूद है एवं दीवार के पास काले रोपे हुए हैं एवं पश्चिम में वादीगण के मकान की दीवार स्थित है। वादीगण उक्त नोहरा में शांतिपूर्वक कदीम से काबिज है एवं उक्त नोहरे में वादीगण के करीब 2 ट्रोली पत्थर पड़े हुए हैं और कुछ बबूल के वृक्ष भी खड़े हैं एवं

Regular First Appeal (Against decree) No:14/2023

Omprakash Vs. Narbda & Ors.

Date of order: 19.3.2026

वादीगण के उत्तरी तरफ उक्त पट्टे की भूमि मार्क ए, बी, ई, एफ स्वर्गीय देवकरण व स्वर्गीय हजारी के बंट में रखी थी जिस पर अभी गणपत मेघवाल का रहवासी मकान निर्मित है एवं प्रतिवादीगण को इस बाबत कोई आपत्ति नहीं है। वादीगण स्वर्गीय चन्द्रा जी की उपरोक्त जायदाद में मार्क ए, बी, सी, डी भू-भाग पर जो उनका बंटसुदा है उस पर काबिज है एवं कदीम से शांतिपूर्वक बिना किसी रोकटोक व बाधा के इसका उपयोग, उपभोग करते आ रहे हैं। लेकिन प्रतिवादीगण जून 2012 से वादीगण के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में नाजायज दखलअंदाजी कर रहे हैं एवं उक्त भूखण्ड (नोहरे) में जबरन काबिज होने को आमादा हो रखें है जिससे वादीगण के लिए स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने हेतु उक्त बाद संस्थित करना आवश्यक हो गया है।”

#### **Written statement of Defendants before Ld.Trial Court**

4. In written statement of Def.no. 1 to 6 it was averred that Najri Naksha[Schedule-A] is wrong and that the Plaintiff's have sold land ad-measuring 2532 Sq.ft which is much more than their share on 10.10.2008 to Ganpatlal Meghwal in contradiction to their one-third share which comes to only 1161.66 Sq.ft area. It was also averred that the construction material at site belongs to Def.no.1 to 6. It is also urged that Plaintiff is not in possession of disputed suit property and rather the buyer-Ganpatlal Meghwal is the owner and thus, this suit is not maintainable.

#### **Issues framed before Ld. Trial Court**

5. The Ld. Trial court has framed the following issues:-

1. आया वाद पत्र में वर्णित स्व. चन्द्राराम जी के नाम जारी पट्टा संख्या 201 दिनांक 29.04.61 में से वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में एबीसीडी वादीगण का बंटसुदा व कब्जासुदा है ? वादीगण
2. आया प्रतिवादीगण वादीगण को तथाकथित एबीसीडी भूखण्ड से जबरन बेदखल पर आमादा है ? वादीगण
3. आया वादीगण ने नजरी नक्शा गलत पेश किया है, पट्टे व नजरी नक्शे की भुजा मेल नहीं खाती है ? प्रतिवादी

Regular First Appeal (Against decree) No:14/2023

Omprakash Vs. Narbda & Ors.

Date of order: 19.3.2026

4. आया वादीगण ने अपने हिस्से में ज्यादा जमीन दिनांक 10.10.08 को गणपत को बेचान कर दी तथा वादी मौके पर काबिज नहीं है ?  
प्रतिवादी
  5. आया वादी का वाद घोषणा व बंटवाड़े के अभाव में स्थाई निषेधाज्ञा वाद पोषणीय है ?  
प्रतिवादी
  6. अनुतोष ?
6. On above issues the plaintiff has got recorded the oral evidence of **PW:1/Omprakash & PW:2/Sohanlal** got exhibited Ex:1/Sale-deed Ex:1/1/Copy of sale-deed, Ex:2 to Ex:6/Photographs of site, Ex:5/copy of notice by Local-commissioner, Ex:6 & EX:7/Local Commissioner Report & Najri Naksa, Ex:8 to Ex:11/color photographs with Mauka-report of Local commissioner, Ex:12/Certified copy of charge-sheet, EX:13/Certified copy of FIR, Ex:14/Certified copy of order-sheet, Ex:15/Certified copy of complaint u/s. 107 Cr.P.C, Ex:16/Certified copy of Application to PS:Harsor, Ex:17/Certified copy of statement of Navratan to Police, Ex:18/Certified copy of statement of Narbada to Police, Application to PS:Harsor, Ex:19 to Ex:20/color photographs & Ex:21/Agreement to sell. No oral or documentary evidence was given by the Defendants.

**Point for Determination**

7. The only point for determination which arises for kind consideration of this court is as to:-  
  
**“Whether the findings returned by Ld. Trial Court on Issue nos.1 to 5 are in accordance with law particularly when the suit for permanent injunction simplicitor was held to be not maintainable in absence of relief of partition ? ”**
8. Ld. Counsel for appellants submits that the Ld. Trial Court had erroneously held the Issue no.1 & 2 to be not proved by the Plaintiff & dismissed the suit for permanent injunction as filed by the Plaintiff's

Regular First Appeal (Against decree) No:14/2023

Omprakash Vs. Narbda & Ors.

Date of order: 19.3.2026

to be not maintainable with material irregularity. Per contra Ld. Counsel for respondents submits that the suit for permanent injunction simplicitor without claiming consequential relief of partition was not maintainable in law and the Ld. Trial court has rightly rejected the same.

9. Under **Order 41 Rule 31 CPC,1908**, first appeal is a valuable right and the parties have a right to be heard both on questions of law and on facts and the judgment in the first appeal must address itself to all the issues of law and fact and decide it by giving reasons in support of the findings. [Vide: **Santosh Hazari Vs. Purushottam Tiwari**, AIR 2001 SC 965 and **Madhukar & Ors. Vs. Sangram and Ors.**, AIR 2001 SC 2171].

Thus, it is evident that the First Appellate Court must decide the appeal giving adherence to the statutory provisions of Order 41 Rule 31 CPC,1908.” Same parameters has been emphasized in case of **Vinod Kumar Vs. Gangadhar** (2015)1 SCC 391.

#### **Analysis of Ld. Trial Court’s Findings on Issue No.1-**

10. As regards the Issue No.1, before the Ld. Trial Court was as under:-

आया वाद पत्र में वर्णित स्व. चन्द्राराम जी के नाम जारी पट्टा संख्या 201 दिनांक 29.04.61 में से वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में एबीसीडी वादीगण का बंटसुदा व कब्जासुदा है ? वादीगण

11. The Ld. Trial court while appreciating this Issue no.1 has recorded a specific findings based on due appraisal of oral & documentary evidence of Plaintiff’s that:-

“वादी पक्ष ने वादपत्र के समर्थन में स्वयं वादी पी.ड. 1 ओमप्रकाश को परीक्षित करवाया है जिसने सशपथ साक्ष्य में वादपत्र में अंकित अभिकथनों की पुनरावृत्ति करते हुए उक्त प्लॉट मार्क ई, एफ, सी, डी का

Regular First Appeal (Against decree) No:14/2023

Omprakash Vs. Narbda & Ors.

Date of order: 19.3.2026

जारीशुदा पट्टा प्रदर्श 1 पेश किया है तथा उक्त प्लॉट का वादग्रस्त भाग मार्क ए बी सी डी वादीगण का बंटशुदाव कब्जाशुदा होना बताया है। इस पारिपेक्ष्य में सर्वप्रथम यह उल्लेखनीय है कि वादपत्र में वादी पक्ष द्वारा यह लेश मात्र अभिकथन नहीं किए गए हैं कि उक्त प्लॉट मार्क ई, एफ, सी, डी का बंटवारा किस प्रकार व किस दिनांक को किया गया है तथा उक्त बंटवारे की विशिष्टियों के संबंध में वादी ओमप्रकाश ने सशपथ साक्ष्य में भी किसी प्रकार के कथन नहीं किए हैं। उक्त वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात प्रदर्श 12 लगायत 18 के अवलोकन से भी वादग्रस्त भूखण्ड मार्क ए बी सी डी पर वादी का बंट व कब्जा होने का तथ्य प्रकट नहीं है। मौका कमिन्तर रिपोर्ट प्रदर्श 7 के अनुसार मौके पर उभयपक्ष की उपस्थिति होना प्रकट है। वादी पक्ष की ओर से परीक्षित अन्य गवाह पी.ड. 2 सोहनलाल वादी की जान-पहचान का होने व वादग्रस्त भूखण्ड पर बचपन से वादी ओमप्रकाश का कब्जा देखने की साक्ष्य देता है। हालांकि उक्त गवाह ने प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि वादग्रस्त प्लॉट का पट्टा उसने नहीं देखा, वह चन्द्रराम रेगर व उसके पुत्रों को नहीं जानता है, उक्त प्लॉट के बंटवारे के संदर्भ में उसे जानकारी नहीं है तथा वह वादी के पिता का नाम भी नहीं जानता है। गवाह ने मौके पर रोपी गयर पट्टिया प्रकाश द्वारा सात-आठ साल पूर्व से रोपे होने का कथन किया है। उक्त प्रकाश होने है, इस बाबत स्पष्ट नहीं किया गया है। इस प्रकार वादग्रस्त भूखण्ड मार्क ए, बी, सी, डी वादी के बंट में उसे प्राप्त हुआ हो तथा उस पर वादी का कब्जा रहा हो, इस संदर्भ में उक्त गवाह को विशिष्ट जानकारी नहीं होना प्रकट है।

हस्तगत प्रकरण में वादपत्र में वादी ने उक्त प्लॉट मार्क ई, एफ, सी, डी उसके पिता का पट्टाशुद होकर वादी व प्रतिवादीगण का उक्त प्लॉट में बराबर 1/3 हिस्सा होना बताया है व बंटवारे में उसे वादग्रस्त भाग मार्क ए, बी, सी, डी प्राप्त होना बताया है। उक्त प्लॉट स्व. चन्द्रराम का पट्टाशुद होने व समस्त पक्षकारान का उस पर 1/3 हिस्सा होने के तथ्य जवाब दावा में प्रतिवादीगण ने स्वीकार किये है। परन्तु बंटवारा होने व बंटवारे में वादग्रस्त भाग मार्क ए, बी, सी, डी वादी को प्राप्त होने से इंकार किया गया है। साक्ष्य के पूर्वोक्त विवेचन से यह प्रकट हुआ है कि वादी ने उक्त बंटवारे के संदर्भ में किसी प्रकार के विशिष्ट अभिकथन वादपत्र में नहीं किए हैं तथा ना ही साक्ष्य में बंटवारे के तथ्य को स्पष्ट किया है। वादी का वादग्रस्त भूखण्ड पर काबिज होने का तथ्य भी वादी की साक्ष्य के पूर्वोक्त विवेचनानुसार साबित नहीं हुआ है।

Regular First Appeal (Against decree) No:14/2023  
 Omprakash Vs. Narbda & Ors.  
 Date of order: 19.3.2026

अतः पत्रावली पर उपलब्ध समग्र साक्ष्य के पूर्वाक्त विवेचनानुसार न्यायालय के विनम्र मत में वादी पक्ष उक्त विवाद्यक संभावना की प्रबलता के आधार पर अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है।”

**Analysis of Ld. Trial Court's Findings on Issue No.5:-**

12. As the Plaintiff's have failed to prove the Issue no.1 before Ld. Trial court, the only Issue which requires consideration before this court is the findings on the Issue No.5, wherein the Ld. Trial Court has taken into consideration the fact that the burden to prove the same was on the Defendants. The Issue no.5 before Ld.Trial court was as under:-

आया वादी का वाद घोषणा व बंटवाड़े के अभाव में स्थाई निषेधाज्ञा वाद पोषणीय है ? प्रतिवादी

13. The Ld. Trial court while appreciating the Issue no.5 have taken the view as under:-

“हस्तगत प्रकरण में वादपत्र में वादी ने उक्त प्लॉट मार्क ई, एफ, सी, डी उसके पिता का पट्टाशुद होकर वादी व प्रतिवादीगण का उक्त प्लॉट में बराबर 1/3 हिस्सा होना बताया है व बंटवारे में उसे वादग्रस्त भाग मार्क ए, बी, सी, डी प्राप्त होना बताया है। उक्त प्लॉट स्व. चन्द्राराम का पट्टाशुद होने व उनके पुत्रों का उसमें बराबर 1/3 हिस्सा होने के तथ्य जवाब दावा में प्रतिवादीगण ने स्वीकार किये है, परन्तु बंटवारा होने व बंटवारे में वादग्रस्त भाग मार्क ए, बी, सी, डी वादी को प्राप्त होने से इंकार किया गया है। साक्ष्य के पूर्वाक्त विवेचन से यह प्रकट हुआ है कि वादी ने उक्त बंटवारे के तथ्य को साबित नहीं किया है, तथा ना ही वादग्रस्त भूखण्ड मार्क ए बी सी डी वादी के स्वामित्व का होने बाबत किसी प्रकार की ठोस साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है। मौके पर वादी का कब्जा होने का तथ्य भी वादी साक्ष्य से साबित नहीं है। वादपत्र में बंटवारा अथवा स्वामित्व घोषणा का अनुतोष भी नहीं चाहा गया है।

ऐसी स्थिति में चूंकि उक्त प्लॉट के बंटवाडा का तथ्य साबित नहीं है, हालांकि उक्त प्लॉट में स्व. चन्द्राराम के तीन पुत्रों का बराबर हिस्सा होने का तथ्य पक्षकारान के मध्य निर्विवादित होना प्रकट हुआ है, अतः उक्त प्लॉट मार्क ई एफ सी डी पक्षकारान का शामिल होना स्वीकृत है। विधि की सुस्थापित व्यवस्था अनुसार मात्र एक सह स्वामी को अन्य सह

Regular First Appeal (Against decree) No:14/2023

Omprakash Vs. Narbda & Ors.

Date of order: 19.3.2026

स्वामी के विरुद्ध बंटवारे/स्वामित्व घोषणा के अभाव में स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष दिया जाना उचित नहीं है।”

14. The Ld. Trial court have further held qua failure of Plaintiff to prove his ownership over the disputed suit land and held that “विधि की यह भी सिद्धान्त है कि मात्र स्थाई निषेधाज्ञा के दावा में वादी के स्वामित्व पर प्रतिवादी पक्ष की ओर से आपत्ति कर दिए जाने की सूरत में यदि वादी का स्वामित्व ठोस रूप से प्रकट/साबित नहीं होता हो तो वादी स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।”
15. The Ld. Trial court have further relied on **Anathula Sudhakar v/s P. Buchi Reddy (dead) by L.Rs. and Ors.** (2008) 4 SCC 594 wherein the Hon'ble Supreme court has outlined the contours of legal position:-
- “To summarise, the position in regard to suits for prohibitory injunction relating to immovable property, is as under:
- (a) **Where a cloud is raised over the Plaintiff's title & he does not have possession, a suit for declaration & possession, with or without a consequential injunction, is the remedy.** Where the Plaintiff's title is not in dispute or under a cloud, but he is out of possession, he has to sue for possession with a consequential injunction. Where there is merely an interference with the Plaintiff's lawful possession or threat of dispossession, it is sufficient to sue for an injunction simpliciter
  - (b) As a suit for injunction simpliciter is concerned only with possession, normally the issue of title will not be directly and substantially in issue. **The prayer for injunction will be decided with reference to the finding on possession.** But in cases where de-jure possession has to be established on the basis of title to the property, as in the case of vacant sites, the issue of title may directly and substantially arise for consideration, as without a finding thereon, it will not be possible to decide the issue of possession.
  - (c) But a finding on title cannot be recorded in a suit for injunction, unless there are necessary pleadings and appropriate issue regarding title...”

Regular First Appeal (Against decree) No:14/2023  
 Omprakash Vs. Narbda & Ors.  
 Date of order: 19.3.2026

उक्त मत की पुनरावृत्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त **T.V. Ramakrishna Reddy vs. M. Mallappa and Ors.** AIR 2021 SC 4293 में भी की है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध समग्र साक्ष्य के पूर्वाक्त विवेचनानुसार न्यायालय के विनम्र मत में स्थापित विधि के अनुसार हस्तगत प्रकरण में वादीगण का दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा बंटवारा अथवा स्वामित्व घोषणा के अभाव में पोषणीय नहीं है।”

16. This court has perused the oral and documentary evidence on record to ascertain as to whether the suit for permanent injunction simplicitor is maintainable in law when a doubt is raised qua the ownership, title and possession of the Plaintiff over the disputed suit-property. If the plaintiff is not found in possession of suit property, than, relief of possession must be sought for & merely suit for permanent injunction would not be maintainable. If the cloud is cast over the title or ownership of the suit property, than a suit for declaration and partition alongwith injunctive relief can be filed.
17. In this case, the Ld. Trial court has recorded a categorical finding that the Plaintiff is neither been able to prove his own possession nor has he been able to prove that a partition had taken place between Plaintiff's family as it is evident from the following findings:-

“मौके पर वादी का कब्जा होने का तथ्य भी वादी साक्ष्य से साबित नहीं है। वादपत्र में बंटवारा अथवा स्वामित्व घोषणा का अनुतोष भी नहीं चाहा गया है।

ऐसी स्थिति में चूंकि उक्त प्लॉट के बंटवाडा का तथ्य साबित नहीं है, हालांकि उक्त प्लॉट में स्व. चन्द्रराम के तीन पुत्रों का बराबर हिस्सा होने का तथ्य पक्षकारान के मध्य निर्विवादित होना प्रकट हुआ है, अतः उक्त प्लॉट मार्क ई एफ सी डी पक्षकारान का शामिल होना स्वीकृत है। विधि की सुस्थापित व्यवस्था अनुसार मात्र एक सह स्वामी को अन्य सह स्वामी के विरुद्ध बंटवारे/स्वामित्व घोषणा के अभाव में स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष दिया जाना उचित नहीं है।”

Regular First Appeal (Against decree) No:14/2023

Omprakash Vs. Narbda & Ors.

Date of order: 19.3.2026

18. This court is of considered view that the findings of Ld. Trial court on Issue no. 1 & 5 are well reasoned, based on due appreciation of oral & documentary evidence on record and the same are not perverse, irrational or suffers from any material irregularity so as to warrant any interference by this court in the instant appeal.
19. In view of the affirmation of findings on Issue no. 1 & 5 as returned by Ld. Trial court, no useful purpose would be served by analysing the findings on ancillary & incidental Issues no. 2 to 4 in view of Order 20 Rule 5 CPC,1908 since the findings on Issue no. 1 & 5 are sufficient for the decision of the suit.
20. Thus, the findings of Ld. Trial court is found to be in tandem with evidence on record and this court finds no infirmity, illegality or any perversity in the same and thus, the same stands affirmed by this court in totality.
21. As a consequence, this court does not find any perceptible merit in the instant First Appeal filed against the impugned final judgment & decree dated 4.8.2023 passed by the Court of Sr. Civil Judge, Merta in Civil Suit No:14/2012 & **consequently, this Regular First appeal stands dismissed & findings of Ld. Trial Court stands affirmed.**
22. Pending applications have become in fructuous in view of disposal of this appeal.
23. Appellate decree be prepared by office of this court.
24. Pronounced in open court & typed by me.
25. Let the Trial court record be sent back.

The File of this Appeal be consigned to records.

19.3.2026

(Arun K Beriwal)